

रिज़र्व बैंक ने 2022-23 के दौरान उधार कार्यक्रमों के आकार से शुरुआती बाजार चिंताओं और यूक्रेन में युद्ध से उत्पन्न अनिश्चित वैश्विक वातावरण से विपरीत परिस्थितियों और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा समकालिक मौद्रिक नीति को सख्त करने के बावजूद गैर-विघटनकारी तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों की बाजार उधार आवश्यकताओं को प्रबंधित किया। वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के लिए बाजार उधार का भारित औसत प्रतिफल, मौद्रिक नीति में समायोजन को कम करने के रुख के बीच, नीतिगत रिपो दर में 250 बीपीएस की संचयी वृद्धि के मुकाबले 104 बीपीएस बढ़ गया। रोलओवर जोखिम को कम करने के लिए बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को बढ़ाया गया था। सॉवरेन हरित बॉण्ड पहली बार केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए थे, जिसके आगम सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में उपयोग किए जाएंगे जो अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने में मदद करती है।

VII.1 रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 तथा 21 के अनुसार केंद्र सरकार और इस अधिनियम की धारा 21ए में किए गए प्रावधान के अनुसार द्विपक्षीय करारों के अनुसरण में 28 राज्य सरकारों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के घरेलू कर्ज का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) में की गई व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को तीन महीने तक की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) के रूप में अल्पावधिक ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को कम किया जा सके।

VII.2 2022-23 में, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में कम था लेकिन यह पूर्व-महामारी के स्तर से ऊपर रहा। वैश्विक मुद्रास्फीति और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को आक्रामक रूप से सख्त करने वाले वातावरण में तदनुसार उधार लेने की आवश्यकताएँ उच्च बनी रहीं, जिसने घरेलू वित्तीय बाजारों पर प्रभाव विस्तार को बढ़ा दिया। जैसा कि यूक्रेन में युद्ध और उच्च वैश्विक खाद्य और कमोडिटी की कीमतों के बाद भारत पर मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण बिगड़ गया, रिज़र्व बैंक ने नीतिगत रिपो दर को संचयी रूप से 250 बीपीएस से बढ़ा दिया और नीतिगत रुख को समायोजन को कम करने की ओर कर दिया।

VII.3 भारतीय जी-सेक बाजार पर वैश्विक और घरेलू वित्तीय स्थितियों में सख्ती के प्रभाव के बावजूद, लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाजार विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए गैर-विघटनकारी तरीके से बाजार उधार कार्यक्रम को पूरा करना सुनिश्चित किया। रिज़र्व बैंक ने वैश्विक प्रभाव विस्तार से प्रतिफल पर दबाव, बढ़ी हुई घरेलू मुद्रास्फीति और अतिरिक्त चलनिधि की क्रमिक वापसी को देखते हुए लगातार अपनी ऋण प्रबंधन कार्यनीति की समीक्षा की और इसे अनुकूल बनाया। वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के लिए बाजार उधारी का भारित औसत प्रतिफल 104 बीपीएस तक बढ़ गया। रोलओवर जोखिम को रोकने के लिए बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को बढ़ाया गया था। केंद्रीय बजट 2022-23 में सरकार की घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार के परामर्श से 2022-23 के दौरान ₹16,000 करोड़ की कुल राशि के लिए सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) जारी किए।

VII.4 अध्याय के शेष भाग तीन खंडों के अंतर्गत हैं। खंड 2 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए ऋण प्रबंधन के क्षेत्रों में वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ 2022-23 की कार्ययोजना के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करता

है। खंड 3 में 2023-24 में की जाने वाली प्रमुख पहलें शामिल हैं, जिसके बाद अंतिम खंड में सारांश दिया गया है।

## 2. 2022-23 के लिए कार्यसूची

VII.5 विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- जी-सेक बाजार में चलनिधि बढ़ाने और नए निर्गम की सुविधा के लिए प्रतिभूतियों को फिर से जारी करने के साथ-साथ कैलेंडर संचालित, नीलामी-आधारित स्विच और वापसी-खरीद परिचालन के माध्यम से ऋण का समेकन (पैराग्राफ VII.6 - VII.9);
- 2005 में जारी प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के लिए समेकित परिचालन दिशानिर्देश समय-समय पर अद्यतन किए जाते हैं। हालांकि, बुनियादी पात्रता मानदंड, जैसे निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) की आवश्यकता और लक्ष्यों से संबंधित दिशानिर्देश, काफी हद तक अपरिवर्तित हैं। पीडी के लिए मौजूदा परिचालन दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव था (पैराग्राफ VII.10);
- देश भर में उपयुक्त खुदरा निवेशकों तक समग्र पहुंच में सुधार के लिए 'आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना' को और लोकप्रिय बनाने के लिए उचित उपाय करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VII.11];
- माननीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2022 को अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में घरेलू बाजार में एसजीआरबी जारी करेगी और आगम को सार्वजनिक-क्षेत्र की हरित परियोजनाओं में लगाया जाएगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक, इसके ऋण प्रबंधक के रूप में, भारत सरकार (जीओआई) को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एसजीआरबी जारी करने के लिए रूपरेखा

तैयार में आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। प्रारंभिक कार्य पूरा करने के बाद वर्ष के दौरान एसजीआरबी जारी करने की परिकल्पना की गई थी (पैराग्राफ VII.12);

- सरकार के सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के लिए मध्यावधि ऋण प्रबंधन कार्यनीति (एमटीडीएस) की समीक्षा, जिसका उद्देश्य जोखिम के विवेकपूर्ण स्तरों और स्थिर ऋण संरचना के साथ मध्यम से दीर्घावधि में कम लागत पर बाजार उधार जुटाना, साथ ही एक अर्थसुलभ और अच्छी तरह से काम कर रहे घरेलू ऋण बाजार का विकास भी करना है। (पैराग्राफ VII.13);
- सामान्य सरकारी ऋण का लगभग एक-तिहाई उप-राष्ट्रीय सरकारों से संबंधित है। हालांकि, उप-राष्ट्रीय सरकार में कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए ऋण प्रबंधन की कार्यनीति को रेखांकित करने वाले एक दस्तावेज की कमी थी। इसलिए, कुछ राज्यों के लिए एक पायलट एमटीडीएस का मसौदा तैयार करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें बाधाओं और संभावित जोखिमों का उचित संज्ञान लेते हुए, उनकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों की योजना को दर्शाया गया था (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VII.14]; और
- नकद और ऋण प्रबंधन में विवेकपूर्ण प्रथाओं के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ VII.15)।

### कार्यान्वयन की स्थिति

VII.6 रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान ₹21,79,392 करोड़ के बराबर केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सकल बाजार उधार को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19.2 प्रतिशत अधिक था।

VII.7 रिजर्व बैंक ने पुनर्खरीद/स्विच के माध्यम से सक्रिय समेकन और पुनर्निर्गम के माध्यम से निष्क्रिय समेकन की अपनी नीति को जारी रखा। 2022-23 के दौरान, जी-सेक के 177 निर्गमों में से 161 पुनर्निर्गम (91 प्रतिशत) थे, जबकि पिछले वर्ष में 154 निर्गमों में से 142 पुनर्निर्गम (92.2 प्रतिशत) थे।

VII.8 दीर्घावधि की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ अल्पावधि में परिपक्व होने वाली सरकारी प्रतिभूतियों के स्विचिंग के माध्यम से ऋण समेकन का सक्रिय रूप आम तौर पर हर महीने में एक बार आयोजित किया जाता है। तदनुसार, ₹1,00,000 करोड़ की बजटीय राशि के मुकाबले ₹1,05,489 करोड़ की राशि के स्विच 2022-23 के दौरान पूरे किए गए।

VII.9 2022-23 के दौरान, विभिन्न परिपक्वता बकेट में विभिन्न निवेशकों की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से 2 से 40 वर्ष की अवधि (मूल परिपक्वता) तक की प्रतिभूतियां जारी की गईं। वर्ष के दौरान 7-वर्ष और 13-वर्ष की अवधि (मूल परिपक्वता) के अस्थायी दर बॉण्ड (एफआरबी) भी फिर से जारी किए गए। 2022-23 के दौरान कुल निर्गमों में एफआरबी की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 7.8 प्रतिशत की तुलना में 2.5 प्रतिशत थी।

VII.10 मास्टर निर्देश- प्राथमिक व्यापारियों के लिए परिचालन दिशानिर्देश 1 जुलाई 2016 को प्रकाशित हुए थे। रिजर्व बैंक इन दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

VII.11 वर्ष के दौरान, 'आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना' की समग्र पहुंच में सुधार के लिए देश भर में कई जन जागरूकता अभियान और निवेशक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। इसके अलावा, पोर्टल को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए 'खुदरा प्रत्यक्ष पोर्टल' के उपयोगकर्ता इंटरफेस फीचर्स में और सुधार किया गया है। इन पहलों के परिणामस्वरूप वर्ष के

दौरान खोले गए खातों की संख्या और योजना के तहत किए गए कुल निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

VII.12 2022-23 की दूसरी छमाही में विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए अर्ध-वार्षिक निर्गम कैलेंडर में ₹16,000 करोड़ के एसजीआरबी के निर्गम को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, भारत सरकार ने 9 नवंबर 2022 को एसजीआरबी फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया। दूसरे पक्ष की राय प्रदाता सीआईसीआईआरओ<sup>1</sup> द्वारा 'अच्छा अभिशासन' स्कोर के साथ फ्रेमवर्क को 'मध्यम हरा' के रूप में मूल्यांकित किया गया था। जनवरी-फरवरी 2023 के दौरान ₹ 8,000 करोड़ प्रत्येक की दो किश्तों में एसजीआरबी निर्गम की नीलामी आयोजित की गई थी (बॉक्स VII.1)।

VII.13 भारत सरकार के ऋण के लिए मध्यावधि ऋण प्रबंधन कार्यनीति (एमटीडीएस) पर इनपुट सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ, भारत सरकार को जानकारी उपलब्ध कराई गई। एमटीडीएस को तीन साल (यानी, 2022-23 से 2024-25) की अवधि के साथ मध्यम अवधि के लिए तैयार किया गया है, जिसकी आम तौर पर अगले तीन वर्षों की रोल-ओवर अवधि के साथ वार्षिक समीक्षा की जाती है।

VII.14 दो राज्य, अर्थात् महाराष्ट्र और तेलंगाना पायलट एमटीडीएस की तैयारी के लिए सहमत हुए हैं। जुलाई 2022 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 32वें सम्मेलन में राज्यों के लिए एमटीडीएस के उद्देश्यों/औचित्य और संरचना पर एक प्रस्तुति दी गई थी। वर्ष के दौरान राज्यों के लिए नकद और ऋण प्रबंधन पर आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों (सीबीपी) के दौरान राज्यों के लिए एमटीडीएस के महत्व और लाभों को भी शामिल किया गया। संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से पायलट एमटीडीएस तैयार किया जा रहा है।

VII.15 आठ राज्यों, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और

<sup>1</sup> सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च (सीआईसीआईआरओ), नॉर्वे 1990 में स्थापित एक बहुविषयक जलवायु अनुसंधान संस्थान है। सीआईसीआईआरओ एक वैश्विक-अग्रणी संस्थान है जो उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान प्रदान करता है जो समाज को जलवायु चुनौती से लड़ने और अंतरराष्ट्रीय जलवायु सहयोग को मजबूत करने में मदद करता है।

## बॉक्स VII.1 भारत के सॉवरेन हरित बॉण्ड

विषयगत बॉण्ड निश्चित-आय वाली प्रतिभूतियां हैं जो पूंजी बाजार में जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, आवास, महासागर और समुद्री संरक्षण, और सतत विकास लक्ष्यों जैसे विशिष्ट विषय से संबंधित परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए वित्तपोषण बढ़ाने के लिए जारी की जाती हैं (विश्व बैंक, 2022)। हरित बॉण्ड एक प्रकार के विषयगत बॉण्ड हैं, अन्य श्रेणियां सामाजिक बॉण्ड, धारणीयता बॉण्ड और धारणीयता संबंधी बॉण्ड हैं।

हरित बॉण्ड के मामले में, आगम का उपयोग विशेष रूप से नई और/या मौजूदा परियोजनाओं को वित्तपोषित या पुनर्वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है, जिनसे पर्यावरण और/या जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद होती है। जबकि हरित बॉण्ड निर्गम कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों/सिद्धांतों द्वारा समर्थित है, अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (आईसीएमए) के हरित बॉण्ड सिद्धांतों (जीबीपी) को व्यापक रूप से स्वैच्छिक प्रक्रिया दिशानिर्देशों के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो पारदर्शिता और प्रकटीकरण की सिफारिश करते हैं और हरित बॉण्ड के विकास में ईमानदारी को बढ़ावा देते हैं।

विश्व बैंक द्वारा पहला हरित बॉण्ड 2008 में जारी किया गया था। धारणीय वित्त के लिए वैश्विक बाजार ने 2014 के बाद से मुख्य रूप से हरित बॉण्ड जारी करने के कारण काफी वृद्धि दर्ज की है। प्रकाशित आंकड़ों (जलवायु बॉण्ड पहल, नवंबर, 2022) के अनुसार, 30 सितंबर 2022 तक संचयी हरित बॉण्ड निर्गम 2.0 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है, जिसमें 26 सॉवरेन द्वारा जारी निर्गमित सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीआरबी) शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 230.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। यूरोपीय राष्ट्र एसजीआरबी के प्रमुख निर्गमकर्ता हैं, जिनमें 5-वर्ष और 10-वर्ष की निर्गम अवधियाँ ज्यादा हैं।

नवंबर 2021 में सीओपी26 के शिखर सम्मेलन<sup>2</sup> में, भारत ने 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की। भारत के संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 45 प्रतिशत कम करने के लक्ष्य शामिल हैं। एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा काफी अधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। केंद्रीय बजट 2022-23 में, भारत सरकार ने घोषणा की कि समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2022-23 के दौरान घरेलू बाजार में एसजीआरबी जारी किए जाएंगे। आगम सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाई जाएगी, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करेगी।

भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक के परामर्श से, आईसीएमए के जीबीपी की तर्ज पर सॉवरेन हरित बॉण्ड फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया और 9 नवंबर 2022 को इसे अधिसूचित किया। यह फ्रेमवर्क सीआईसीआईआरओ द्वारा बाहरी समीक्षा के अधीन था। इसने भारत के हरित बॉण्ड फ्रेमवर्क को 'अच्छे' अभिशासन के साथ 'मध्यम हरित' के रूप में रेट किया। फ्रेमवर्क विभिन्न पर्यावरणीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त हरित परियोजनाओं की नौ व्यापक श्रेणियों को सूचीबद्ध करता है जैसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करना, जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करना। सरकार ने विभिन्न उपयुक्त हरित परियोजनाओं के मूल्यांकन और चयन तथा फ्रेमवर्क से संबंधित अन्य प्रासंगिक कार्यों के लिए एक 'हरित वित्त कार्य समिति' का गठन किया है। यह फ्रेमवर्क आगम के आंबटन और इसके पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन का प्रावधान करता है। ग्रीन बॉण्ड जारी करने से प्राप्त आगम का आवंटन और उपयोग भी लेखापरीक्षा के अधीन होगा।

2022-23 के दौरान एसजीआरबी का कुल निर्गमन ₹16,000 करोड़ रखा गया था, जिसमें 25 जनवरी 2023 और 9 फरवरी 2023 को प्रत्येक ₹8,000 करोड़ की दो किश्तों में जारी किया गया था, जिसमें प्रत्येक किश्त में ₹4,000 करोड़ के लिए 5-वर्ष और 10-वर्षीय एसजीआरबी शामिल थे। एसजीआरबी के दोनों चरणों की नीलामी ने बाजार सहभागियों से 5-वर्षीय एसजीआरबी के लिए 3.04 के औसत प्राप्त-स्वीकृत बोली अनुपात और 10-वर्ष के एसजीआरबी के लिए 3.93 के साथ मजबूत मांग दर्ज की। 5-वर्ष और 10-वर्ष के एसजीआरबी के लिए औसत उच्चतम प्रतिफल क्रमशः 4.26 बीपीएस और 3.53 बीपीएस थे, जो संबंधित अवधि की पारंपरिक सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित द्वितीयक बाजार प्रतिफल से कम थे।

### संदर्भ:

1. विश्व बैंक (2022), 'सॉवरेन ग्रीन, सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी बॉण्ड्स: अनलॉकिंग द पोटेंशियल फॉर इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़', विश्व बैंक, अक्टूबर 2022।
2. हैरिसन, सी., मैकगियोच, एम. (2022), 'सस्टेनेबल डेट मार्केट समरी', क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव, नवंबर 2022।

केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में विवेकसम्मत नकद और ऋण प्रबंधन के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक बनाने के लिए

राज्य-वार सीबीपी आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, 14 राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के

<sup>2</sup> 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आमतौर पर सीओपी26 के रूप में संदर्भित किया जाता है, 31 अक्टूबर-13 नवंबर 2021 के दौरान ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटिश इवेंट केंपस (एसईसी) में आयोजित 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था।

लिए दिसंबर 2022 में रिजर्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे में नकद और ऋण प्रबंधन पर दो दिवसीय सीबीपी आयोजित किया गया था।

### प्रमुख गतिविधियां

#### केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.16 2022-23 के दौरान, दिनांकित जी-सेक के माध्यम से भारत सरकार का सकल बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 26.04 प्रतिशत अधिक था। दिनांकित जी-सेक के माध्यम से निवल बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 28.4 प्रतिशत बढ़ गया। दिनांकित जी-सेक के माध्यम से निवल बाजार उधार ने केंद्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) [संशोधित अनुमान] का 63.1 प्रतिशत वित्तपोषित किया, जबकि पिछले वर्ष में जीएफडी (वास्तविक) का 54.5 प्रतिशत किया था। दिनांकित प्रतिभूतियों और टी-बिलों के माध्यम से निवल बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 26.4 प्रतिशत बढ़ गया (सारणी VII.1)।

#### ऋण प्रबंधन परिचालन

VII.17 वर्ष के दौरान जी-सेक निर्गम के भारत औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) में पिछले वर्ष की तुलना में 104 बीपीएस की वृद्धि

### सारणी VII.1: केंद्र सरकार के निवल बाजार उधार

(₹ करोड़)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
निवल बाजार उधार (i से iv)	5,11,500	13,75,654	9,29,351	11,74,375
i) दिनांकित प्रतिभूतियाँ <sup>@</sup>	4,73,972	11,43,114	8,63,103	11,08,261
ii) 91-दिवसीय टी-बिल	-9,600	10,713	45,439	-23,798
iii) 182-दिवसीय टी-बिल	38,354	-18,743	71,252	52,426
iv) 364- दिवसीय टी-बिल	8,774	2,40,570	-50,444	37,487

<sup>@</sup>: वापसी-खरीद/स्विच के लिए समायोजित किए बिना। वापसी-खरीद/स्विच के लिए समायोजन के बाद, 2022-23 के दौरान निवल बाजार उधार ₹11,71,951 करोड़, 2021-22 में ₹9,29,060 करोड़, 2020-21 में ₹11,46,739 करोड़ और 2019-20 में ₹4,73,990 करोड़ रहा।  
स्रोत: आरबीआई।

हुई। संपूर्ण बकाया ऋण स्टॉक पर भारत औसत कूपन में भी 15 बीपीएस की वृद्धि हुई। प्राथमिक निर्गमों (स्विच नीलामी के अंतर्गत निर्गमों को छोड़कर) की भारत औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) पिछले वर्ष के 16.99 वर्षों की तुलना में 16.05 वर्ष रही। बकाया ऋण का डब्ल्यूएएम 11.71 वर्ष से बढ़कर 11.94 वर्ष हो गया (सारणी VII.2)।

### सारणी VII.2: केंद्र सरकार के बाजार ऋण - एक रूपरेखा\*

(प्रतिफल प्रतिशत में/परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में प्रतिफल की अंतिम सीमा का विस्तार			वर्ष के दौरान जारी <sup>^</sup>			बकाया स्टॉक <sup>#</sup>	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारत औसत प्रतिफल	परिपक्वता की सीमा <sup>@</sup>	भारत औसत परिपक्वता	भारत औसत परिपक्वता	भारत औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016-17	6.85-7.46	6.13-7.61	6.46-7.87	7.15	5-38	14.76	10.65	7.99
2017-18	7.23-7.27	6.42-7.48	6.68-7.67	6.97	5-38	14.13	10.62	7.76
2018-19	6.56-8.12	6.84-8.28	7.26-8.41	7.77	1-37	14.73	10.40	7.81
2019-20	5.56-7.38	6.18-7.44	5.96-7.77	6.85	1-40	16.15	10.72	7.71
2020-21	3.79-5.87	5.15-6.53	4.46-7.19	5.79	1-40	14.49	11.31	7.27
2021-22	4.07-5.10	4.04-6.78	4.44-7.44	6.28	1-40	16.99	11.71	7.11
2022-23*	5.43-7.45	5.21-7.52	5.65-7.90	7.32	1-40	16.05	11.94	7.26

<sup>@</sup>: निर्गम की अवशिष्ट परिपक्वता और आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।

\*: विशेष प्रतिभूतियों को छोड़कर।

<sup>^</sup>: स्विच नीलामी को छोड़कर।

<sup>#</sup>: स्विच नीलामी सहित।

स्रोत: आरबीआई

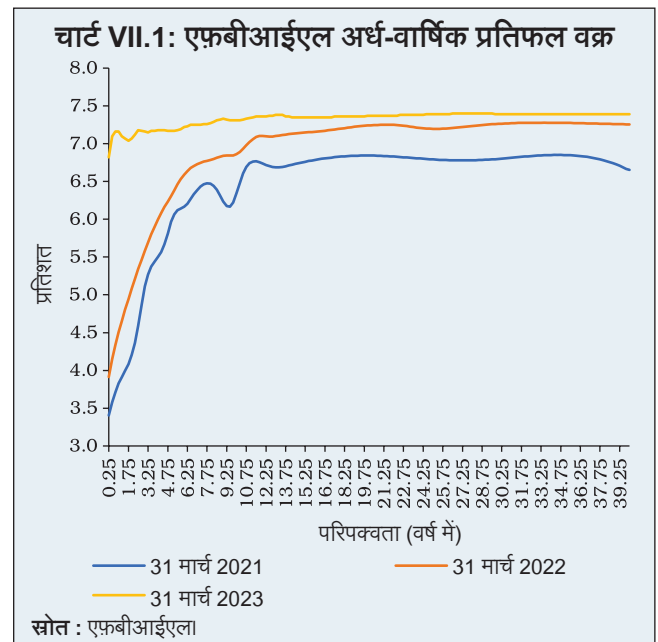


VII.18 पीडी पर आंशिक न्यागमन 2021-22 के सत्रह किशतों में ₹97,938 करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान आठ किशतों में ₹23,053 करोड़ की राशि का हुआ। पिछले वर्ष ₹99,000 करोड़ की कुल अधिसूचित राशि के नौ किशतों की तुलना में ₹16,000 करोड़ की कुल अधिसूचित राशि के लिए चार किशतों पर कोई बोली स्वीकार नहीं की गई थी।

VII.19 जी-सेक प्रतिफल वर्ष के दौरान मुख्य रूप से वैश्विक खाद्य और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और साथ ही प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करने के प्रभाव विस्तार के कारण लगातार नीतिगत दरों में बढ़ोतरी से घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि की वजह से बढ़ गया। मार्च 2022 के अंत में 6.84 प्रतिशत से 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 47 बीपीएस बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 7.31 प्रतिशत हो गया। मई 2022 में रिज़र्व बैंक द्वारा 40 बीपीएस की ऑफ-साइकल दर वृद्धि और 50 बीपीएस की सीआरआर वृद्धि और जून में 50 बीपीएस की दर वृद्धि के साथ-साथ मौद्रिक नीति के समायोजन को कम करने के रुख के कारण 2022-23 की पहली तिमाही में प्रतिफल में तेजी से वृद्धि हुई। अप्रैल और मई की उच्च सीपीआई मुद्रास्फीति ने प्रतिफल पर भी भार डाला। 30 जून 2022 को 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल पहली तिमाही में 61 बीपीएस की बढ़ोतरी के साथ 7.45 प्रतिशत पर बंद हुआ। दूसरी तिमाही में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती वृद्धि चिंताओं के कारण अमेरिकी प्रतिफल और कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट और वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारतीय जी-सेक को शामिल करने की अपेक्षाओं को देखते हुए जुलाई और अगस्त के दौरान सामान्य तौर पर प्रतिफल में गिरावट आई। हालांकि, यूएस फेड की 75 बीपीएस की दर वृद्धि और इसके सख्त निदेशन जिसके कारण अमेरिकी खज़ाना प्रतिफल में वृद्धि हुई इसे देखते हुए प्रतिफल की प्रवृत्ति बदल गई और सितंबर में इसमें वृद्धि हुई। दूसरी तिमाही के दौरान 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 5 बीपीएस की मामूली गिरावट के साथ 7.40 प्रतिशत पर बंद हुआ। तीसरी तिमाही में, शुरुआत में सितंबर की अपेक्षाओं से अधिक घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति को देखते हुए प्रतिफल में वृद्धि हुई। हालांकि, अपेक्षाओं-से-कम अमेरिकी सीपीआई प्रिंट जारी होने और वैश्विक मांग में कमी के प्रति चिंताओं के बीच कच्चे तेल की

कीमतों में गिरावट के बाद अमेरिकी प्रतिफल में आई काफी हद तक नरमी को देखते हुए नवंबर में प्रतिफल में तेजी से गिरावट आई। दिसंबर के दौरान प्रतिफल बढ़ा क्योंकि यूएस फेड ने 2023 के लिए अपने अंतिम ब्याज दर अनुमान को बढ़ा दिया। 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल तीसरी तिमाही में 7 बीपीएस कम होकर 7.33 प्रतिशत पर बंद हुआ। 2023-24 के लिए अपेक्षा से कम सरकारी बाजार उधार की केंद्रीय बजट घोषणा के बाद चौथी तिमाही की शुरुआत में प्रतिफल में गिरावट आई। मूल मुद्रास्फीति के बने रहने और दर वृद्धि चक्र में ठहराव के कोई भावी संकेत नहीं होने की चिंताओं के बीच समायोजन के रुख को कम करने जिसे बाज़ार भागीदारों ने सख्त माना और नीतिगत रिपो दर में 25 बीपीएस की वृद्धि करने के मौद्रिक नीति समिति के फैसले की वजह से प्रतिफल बढ़ गया। अमेरिकी खज़ाना प्रतिफल में गिरावट के चलते मार्च में प्रतिफल में गिरावट आई। 31 मार्च 2023 को 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल चौथी तिमाही में 2 बीपीएस की मामूली गिरावट के साथ 7.31 प्रतिशत पर बंद हुआ। (चार्ट VII.1)।

VII.20 2022-23 के दौरान, बाजार उधार का लगभग 48.9 प्रतिशत पिछले वर्ष के 58.2 प्रतिशत की तुलना में 10-वर्षीय और उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करके जुटाया गया था। इसके अलावा,



**सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम - परिपक्वता स्वरूप**

(राशि ₹ करोड़ में)

अवशिष्ट परिपक्वता	2020-21		2021-22		2022-23	
	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्षों से कम	3,91,990	28.6	2,29,255	20.3	2,70,000	19.0
5 - 9.99 वर्ष	3,07,405	22.4	2,41,865	21.5	4,56,000	32.1
10-14.99 वर्ष	3,76,766	27.5	3,20,639	28.4	2,86,000	20.1
15 -19.99 वर्ष	-	-	-	-	-	-
20 वर्ष और अधिक	2,94,162	21.5	3,35,621	29.8	4,09,000	28.8
<b>कुल</b>	<b>13,70,324</b>	<b>100.0</b>	<b>11,27,382</b>	<b>100.0</b>	<b>14,21,000</b>	<b>100.0</b>

- : शून्य।

**टिप्पणी:** संख्याओं का पूर्णांकन करने के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग के बराबर नहीं हो सकते हैं।

**स्रोत :** आरबीआई

बीमा कंपनियों और भविष्य निधि जैसे दीर्घकालिक निवेशकों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 30-वर्ष और 40-वर्ष की अवधि की प्रतिभूतियां निर्गमित/पुनर्निर्गमित की गईं (सारणी VII.3)

**खज़ाना बिल**

VII.21 केंद्र सरकार की अल्पकालिक नकद आवश्यकताओं को खज़ाना बिल (टी-बिल) जारी करके पूरा किया जाता है। खज़ाना-बिल (91, 182 और 364 दिन) के माध्यम से सरकार का निवल अल्पकालिक बाजार उधार पिछले वर्ष के ₹66,248 करोड़ की तुलना में 2022-23 के दौरान मामूली रूप से घटकर ₹66,114 करोड़ हो गया।

**प्रतिभूतियों का स्वामित्व**

VII.22 वाणिज्यिक बैंक दिसंबर 2022 के अंत तक 37.5 प्रतिशत के साथ सरकारी प्रतिभूतियों [खज़ाना बिल और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों<sup>3</sup> (एसजीएस) सहित] के सबसे बड़े धारक बने रहे, इसके बाद बीमा कंपनियों (25.2 प्रतिशत), रिजर्व बैंक (9.2 प्रतिशत) और भविष्य निधि (9.8 प्रतिशत) थी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की हिस्सेदारी 0.9 प्रतिशत

रही। सरकारी प्रतिभूतियों (खज़ाना बिल और एसजीएस सहित) के अन्य धारकों में म्यूचुअल फंड, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थान (एफआई) और कॉर्पोरेट शामिल हैं।

**प्राथमिक डीलर (पीडी)**

VII.23 पीडी की संख्या 21 [14 बैंक-पीडी और 7 स्वचलित पीडी (एसपीडी)] थी। पीडी के पास दिनांकित जी-सेक की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी का अधिकार है जबकि उनके पास टी-बिल/नकद प्रबंधन बिल (सीएमबी) की प्राथमिक नीलामी के संबंध में बोली प्रतिबद्धता और सफलता अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है। प्राथमिक व्यापारियों ने व्यक्तिगत रूप से खज़ाना बिलों की प्राथमिक नीलामी में 40 प्रतिशत का निर्धारित न्यूनतम सफलता अनुपात हासिल किया। पिछले वर्ष के 71.4 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 के दौरान खज़ाना बिल/सीएमबी की नीलामी में प्राथमिक व्यापारियों की हिस्सेदारी 68.98 प्रतिशत थी। 2022-23 के दौरान दिनांकित जी-सेक की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी के लिए जीएसटी छोड़कर, पीडी को भुगतान किया गया कमीशन, 2021-22 के दौरान ₹412.7 करोड़ की तुलना में ₹91.08 करोड़ था।

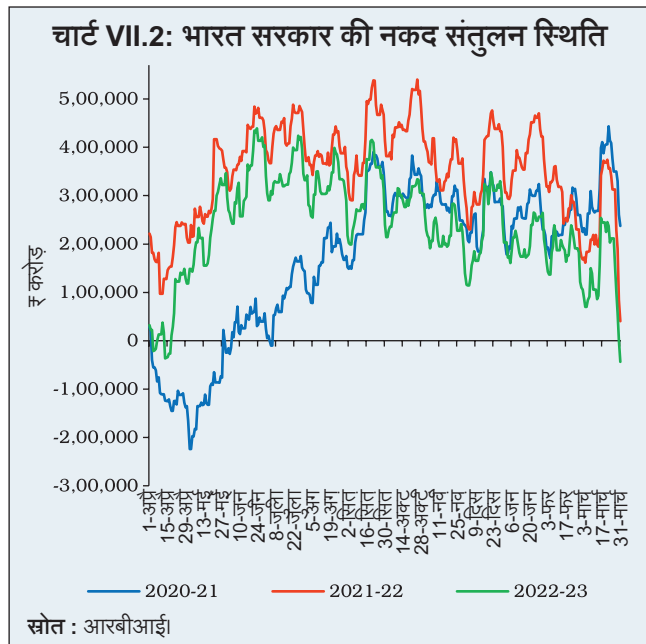
<sup>3</sup> Refer to footnote 31 of Chapter II of this Report.

**सॉवरेन हरित बॉण्ड (एसजीबी) योजना**

VII.24 रिजर्व बैंक ने, भारत सरकार के परामर्श से, 2022-23 के लिए एसजीबी के चार चरणों वाले कैलेंडर की घोषणा की। वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाई गई कुल राशि ₹6,551 करोड़ (12.26 टन) थी। नवंबर 2015 में एसजीबी योजना की शुरुआत के बाद से 63 चरणों के माध्यम से कुल ₹ 45,243 करोड़ (102.63 टन) जुटाए गए हैं।

**केंद्र सरकार का नकद प्रबंधन**

VII.25 केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 की शुरुआत ₹40,352 करोड़ के नकद शेष के साथ की। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, केंद्र की डब्ल्यूएमए सीमा 2022-23 की पहली छमाही के लिए ₹1,50,000 करोड़ तय की गई थी। इसके अलावा, दूसरी छमाही के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा ₹50,000 करोड़ निर्धारित की गई थी। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष में शून्य डब्ल्यूएमए/ओडी की तुलना में 2022-23 के दौरान 9 दिनों के लिए डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट (ओडी) का सहारा लिया। वर्ष के अधिकांश भाग में, केंद्र सरकार का नकद शेष मजबूत कर प्रवाह के साथ सहज बना रहा (चार्ट VII.2)।



**विदेशी केंद्रीय बैंक योजना के तहत निवेश**

VII.26 विदेशी केंद्रीय बैंक (एफसीबी) योजना के तहत, रिजर्व बैंक भारतीय जी-सेक के द्वितीयक जी-सेक बाजार में चुनिंदा एफसीबी और बहुपक्षीय विकास संस्थानों की ओर से निवेश करता है। पिछले वर्ष के ₹3,285 करोड़ (अंकित मूल्य) की तुलना में 2022-23 के दौरान इन संस्थानों की ओर से कुल लेनदेन की मात्रा ₹4,805 करोड़ (अंकित मूल्य) रही।

**राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन**

VII.27 राज्यों को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) वित्तपोषण सुविधा (दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) से बाहर करने की 14वें वित्त आयोग (एफसी) की सिफारिशों के बाद, राज्यों की बाजार उधारी पिछले कुछ वर्ष से बढ़ रही है। राज्यों के जीएफडी के वित्तपोषण में बाजार उधार की हिस्सेदारी 2021-22 (आरई) में 68.1 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 (बीई) में 78.1 प्रतिशत हो गई।

VII.28 राज्यों की सकल और निवल बाजार उधारी पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। 2022-23 में राज्यों की सकल बाजार उधारी राज्य सरकारों द्वारा बाजार उधारी के लिए तिमाही सांकेतिक कैलेंडर में दर्शाई गई राशि का 76 प्रतिशत थी। 2022-23 में 605 निर्गम थे, जिनमें से 45 पुनर्निर्गम थे (2021-22 में 608 निर्गम, जिनमें से 60 पुनर्निर्गम थे) [सारणी VII.4]

VII.29 2022-23 के दौरान एसजीएस निर्गमों का भारित औसत उच्चतम प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) पिछले वर्ष के 6.98 प्रतिशत की तुलना में 7.71 प्रतिशत अधिक था। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलनीय परिपक्वता पर एसजीएस निर्गम का भारित औसत स्प्रेड (डब्ल्यूएस) पिछले वर्ष के 40.95 बीपीएस की तुलना में 2022-23 में 31 बीपीएस पर कम था। 2022-23 में, इक्कीस राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों ने 10-वर्ष के अलावा 2 से 35 वर्ष तक की अवधि की दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी कीं। सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने एक या अधिक नीलामियों में सभी बोलियों को खारिज किया। 10-वर्षीय अवधि (नए निर्गम) की प्रतिभूतियों पर औसत अंतरराज्यीय



**सारणी VII.4: एसजीएस के माध्यम से राज्यों का बाजार उधार**

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5
वर्ष के दौरान परिपक्वता	1,47,067	1,47,039	2,09,143	2,39,562
अनुच्छेद 293(3) के तहत सकल संस्वीकृती	7,12,744	9,69,525	8,95,166	8,80,779
वर्ष के दौरान जुटाई गई सकल राशि	6,34,521	7,98,816	7,01,626	7,58,392
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	4,87,454	6,51,777	4,92,483	5,18,830
कुल स्वीकृतियों की तुलना में वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि (प्रतिशत)	89.0	82.4	78.4	86.1
बकाया देयताएं (अवधि के अंत में) #	32,65,989	39,25,555	44,29,957	49,29,079

#: उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) और अन्य विशेष प्रतिभूतियों सहित  
स्रोत : आरबीआई

स्प्रेड 2021-22 के 4 बीपीएस की तुलना में 2022-23 में 3 बीपीएस था।

VII.30 मौजूदा डब्ल्यूएमए सीमाओं की समीक्षा करने और कोविड-19 प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाने को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के लिए ओवरड्राफ्ट (ओडी) के लिए डब्ल्यूएमए सीमाएं और समय-सीमा तय की जाए जैसा कि 'राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम' पर सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) ने सिफारिश की थी, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। तदनुसार, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा ₹47,010 करोड़ निर्धारित की गई थी। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश लगातार 14 दिनों तक ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं और एक तिमाही में अधिकतम 36 दिनों तक ओडी में रह सकते हैं। 2022-23 के दौरान, सत्रह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ उठाया, बारह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया और ग्यारह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ओडी का लाभ उठाया।

VII.31 वर्षों से, राज्य मध्यवर्ती खजाना बिलों (आईटीबी) के रूप में भारी मात्रा में नकद अधिशेष जमा कर रहे हैं। आईटीबी और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) में राज्यों के बकाया निवेश में वर्ष 2022-23 के दौरान कमी आई (सारणी V.II.5)।

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) / गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) में निवेश

VII.32 रिजर्व बैंक राज्यों की ओर से दो आरक्षित निधि योजनाओं का प्रबंधन करता है - समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)। अब तक, 24 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी, पुडुचेरी ने सीएसएफ की शुरुआत की है। वर्तमान में, 19 राज्य जीआरएफ के सदस्य हैं। एसडीएफ के माध्यम से सीएसएफ और जीआरएफ में अपने वृद्धिशील वार्षिक निवेश के बदले रिजर्व बैंक से रियायती दर पर निधि प्राप्त कर सकते हैं। 31 मार्च 2023 तक सीएसएफ और जीआरएफ में सदस्य राज्यों द्वारा बकाया निवेश क्रमशः ₹1,84,029 करोड़ और ₹10,839 करोड़ था, जबकि मार्च 2022 के अंत में ₹1,54,255 करोड़ और ₹9,399 करोड़ था।

**सारणी VII.5: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश**

(₹ करोड़)

मद	31 मार्च को बकाया				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
14-दिवसीय (आईटीबी)	1,22,084	1,54,757	2,05,230	2,16,272	2,12,758
एटीबी	73,927	33,504	41,293	87,400	58,913
<b>कुल</b>	<b>1,96,011</b>	<b>1,88,261</b>	<b>2,46,523</b>	<b>3,03,672</b>	<b>2,71,671</b>
स्रोत : आरबीआई।					

VII.33 ओडिशा सरकार से प्राप्त एक अनुरोध पर, एक बजट स्थिरीकरण कोष स्थापित किया गया है जो राज्य के बजट पर राजस्व आघात के जोखिम शमन में राज्य की जरूरतों को पूरा करेगा। कोष का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था पर अस्थिर राजस्व के प्रभाव को कम करना है।

### 3. 2023-24 की कार्यसूची

VII.34 केंद्रीय बजट 2023-24 में, 2023-24 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधार का बजट 2022-23 (संशोधित अनुमान) में ₹14,21,000 करोड़ की तुलना में ₹15,43,000 करोड़ रखा गया है। निवल बाजार उधार (टी-बिल सहित) का बजट ₹12,30,911 करोड़ है, जो 2023-24 में जीएफडी के 68.89 प्रतिशत का वित्तपोषण करता है।

VII.35 वर्ष 2023-24 के दौरान, ऋण प्रबंधन के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतिक लक्ष्यों के साथ बाजार उधार कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है:

- जी-सेक बाजार में चलनिधि बढ़ाने और नए निर्गमों की सुविधा के लिए प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम के साथ-साथ कैलेंडर संचालित, नीलामी-आधारित स्विच परिचालन के माध्यम से ऋण का समेकन;
- 'खुदरा प्रत्यक्ष योजना' के तहत खुदरा निवेशकों के लिए पहुँच को और आसान बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन का विकास;

- आरबीआई की 'खुदरा प्रत्यक्ष योजना' के बारे में खुदरा निवेशक जागरूकता बढ़ाने के लिए उचित उपाय करना;
- विदेशी केन्द्रीय बैंकों से लेनदेन की सुविधा के लिए विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) मॉड्यूल का कार्यान्वयन;
- आरबीआई के डेटा वेयरहाउस प्रणाली में सरकारी ऋण सांख्यिकी के कवरेज का विस्तार; और
- नकद और ऋण प्रबंधन में विवेकपूर्ण प्रथाओं के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन।

### 4. निष्कर्ष

VII.36 मुद्रास्फीति में वैश्विक वृद्धि, केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को एक साथ सख्त करने, और कमोडिटी की कीमतों पर यूक्रेन पर युद्ध के लंबे समय तक प्रभाव के कारण लगातार अनिश्चित समष्टिआर्थिक स्थितियों के बीच, 2022-23 के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के बाजार उधार सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। चूंकि वैश्विक अनिश्चितता जारी है, केंद्र के बजटीय राजकोषीय घाटे के कम रहने के बावजूद बाजार उधारी के लिए चुनौतियां बनी रहने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक सरकारों के लिए स्थिर ऋण संरचना सुनिश्चित करते हुए ऋण प्रबंधन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप सरकारी उधार कार्यक्रम को सुचारु रूप से पूरा करने का प्रयास करेगा।